चीन को धैर्य तो दिखाया, अब दम भी दिखाइए

चीन के नए प्रधानमंत्री ली चिंग की प्रस्तावित यात्रा को लेकर भारत में बड़ा उत्साह जगा था। आखिरकार उन्होंने अपनी पहली विदेश यात्रा के रूप में भारत को चुना था जो एक सकारात्मक घटना थी। शायद चीन इस यात्रा के जरिए भारत को यह संदेश भेजना चाहता था कि वह हमारे साथ अपने संबंधों को कितनी अहमियत देता है। लेकिन लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के इस पार दौलत बेग ओल्डी क्षेत्र में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) की घुसपैठ और उसके बाद इस विवाद को सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने में चीन की अनिच्छा ने उस 'अच्छे उद्देश्य' पर संदेह खड़े कर दिए हैं। चीनी घुसपैठ को एक स्थानीय मुद्दे के रूप में पेश करने की भारत सरकार की तमाम कोशिशों और सतर्कतापूर्ण रवैए के बावजूद नई दिल्ली में यह संदेह मजबूत होता जा रहा है कि श्री चिंग की यात्रा और पीएलए की घुसपैठ के बीच कोई संबंध हो सकता है। भारत-चीन सीमा पर घुसपैठ की घटनाएँ असामान्य नहीं हैं लेकिन मौजूदा घटना दो मायनों में अलग है। एक, पंद्रह अप्रैल से शुरू हुई घुसपैठ का लंबे समय तक जारी रहना और दो, घुसपैठ का दायरा जो एलएसी के १९ किलोमीटर भीतर है। यह संकेत देता है कि इस घुसपैठ की योजना स्थानीय स्तर पर नहीं बल्कि पेईचिंग में बनी होगी।

चीन के साथ मौजूदा टकराव के संदर्भ में सरकार को सिर्फ दबाव में आकर फैसला करने की जरूरत नहीं है और न ही युद्ध का माहौल बनाने की। लेकिन उसे मजबूती से यह संदेश जरूर भेजना चाहिए कि भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है और वह दबने के लिए तैयार नहीं है।

अगर यह एक स्थानीय घटना होती तो समाधान में इतना समय नहीं लगता। खासकर भारतीय विदेश मंत्री सलमान खुर्शीद की नौ मई से शुरू होने वाली चीन यात्रा और इस महीने के अंत में श्री चिंग की प्रस्तावित भारत यात्रा को देखते हुए। लेकिन स्थानीय स्तर पर हुई फ्लैग मीटिंग्स के नाकाम रहने और चीनी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता द्वारा बार-बार यह दावा किए जाने से कि चीनी सैनिक उनके अपने इलाके में ही हैं, यह संकेत मिलता है कि चीन को आपसी तनाव दूर करने की जल्दी नहीं है। चीन सरकार ने श्री खुर्शीद की यात्रा की पुष्टि करने में भी सामान्य से ज्यादा समय लगाया। ऐसे में यह धारणा बनाने की गुंजाइश कम है कि पीएलए की कार्रवाई और चीनी राजनैतिक नेतृत्व के रुख में कोई सामंजस्य नहीं हैं। कुछ विश्लेषकों को लगता है कि चीन इस घटना का इस्तेमाल भारत पर अपनी शर्तें थोपने और वार्ताओं के दौरान सौदेबाजी के लिए कर सकता है। ऐसे में पीएलए की घुसपैठ की टाइमिंग 'संयोगवश' नहीं बल्कि रणनीतिक हो सकती है। जाहिर है कि चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा ने उम्मीदें और उत्साह तो नहीं जगाया, उल्टे उस देश के मंसूबों पर संदेह पैदा कर दिए हैं। याद रहे, सन १९५९ में भी चीन ने इसी तरह तीन इलाकों में घुसपैठ की थी और धीरे-धीरे हजारों किलोमीटर जमीन पर कब्जा कर लिया था जिसकी परिणति १९६२ के भारत-चीन युद्ध में हुई थी।

प्राय: सीमा से जुड़े मुद्दों पर चीन की तरफ से भारत पर अति-संवेदनशील रवैए का आरोप लगाया जाता रहा है। लेकिन इस बार यह आरोप लगाने का कोई कारण नहीं है क्योंकि भारत सरकार ने लद्दाख की घटना पर अधिकतम धैर्य का परिचय दिया है। प्रधानमंत्री ने जहाँ इसे 'स्थानीय घटना' बताया, वहीं विदेश मंत्री ने इसे एक छोटा से मुँहासे जैसी समस्या करार दिया जो सही बाम लगाने से ठीक हो जाएगी। भारत ने इस साल के अंत में दोनों देशों की सेनाओं के साझा आतंकवाद निरोधी अभ्यास के प्रति प्रतिबद्धता जताई है और पिछले दिनों चीन में हुए मई दिवस के कार्यक्रम में भारतीय सैनिक अधिकारियों ने हिस्सा लिया है। स्पष्ट है कि भारत अपनी ओर से माहौल बिगाड़ने नहीं बल्कि सुधारने में दिलचस्पी रखता है।

लेकिन अब वह विपक्षी दलों और खुद कांग्रेस के भारी दबाव में है, जिन्हें लगता है कि सरकार ने चीन के सामने कमजोरी का परिचय दिया है। मीडिया निरंतर भारत की उस मानसिकता के कारणों की पड़ताल में जुटा है जिसके चलते वह इतना ताकतवर होने के बाद भी चीन के सामने दबता रहा है। कई शहरों में चीनी घुसपैठ और ढीली-ढाली सरकारी प्रतिक्रिया के खिलाफ प्रदर्शन हुए हैं। कहा जाता है कि सेना भी लद्दाख में रणनीतिक जवाब देने के हक में है, सामान्य भाषा में जिसका अर्थ होगा- जमीनी स्तर पर अपनी ताकत दिखाना। कई पूर्व सेनाध्यक्षों ने कहा है कि सरकार को अपने सैन्य कमांडरों में भरोसा रखना चाहिए और उन्हें जरूरी कदम उठाने की छूट देनी चाहिए।

चीनी सेना का रुख

चीनी प्रधानमंत्री की यात्रा से पहले हुई घुसपैठ के पीछे कई किस्म की थ्योरीज सामने आ रही हैं, जिनमें चीनी नेतृत्व में मतभेद जैसे बिंदु भी उठाए गए हैं, और सेना तथा सरकार का एजेंडा अलग-अलग होने की बात कही गई है। भारत के संदर्भ में पीपुल्स लिबरेशन आर्मी का रुख सरकार की तुलना में अधिक कठोर रहा है और कश्मीरी नागरिकों को स्टेपल किए वीजा जारी करने जैसी घटनाओं के पीछे उसी का हाथ माना जाता रहा है। लेकिन पीएलए अपने प्रधानमंत्री की यात्रा को नाकाम करने की हद तक जाना चाहेगी, इस पर विश्वास करना मुश्किल है। दूसरे, ताजा घटना पर चीनी रक्षा मंत्रालय और विदेश मंत्रालय का रुख करीब-करीब एक सा है।

बताया जाता है कि तीसरी फ्लैग मीटिंग में चीनी फौजी अफसरों ने मांग की कि भारत पूर्वी लद्दाख में बनाई सुविधाओं को खत्म करे, जिनमें सड़कें और बंकर शामिल हैं। भारत ने यह मांग नहीं मानी क्योंकि खुद चीन भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सड़कों, रेल लाइनों और हवाई पट्टियों का जाल बिछा चुका है। अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ी चुनौती के जवाब में भारत निष्क्रिय बैठे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता जिसके ३८ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पहले ही चीन ने कब्जा कर रखा है।

स्पष्ट है कि भारत सरकार चीन को माकूल जवाब देने के भारी दबाव में है। लेकिन यह माकूल जवाब कैसा हो? मुलायम सिंह यादव का 'चीनियों को खदेड़ बाहर करने का फार्मूला' सही है या राजनैतिक-रणनीतिक दबाव डालने का? या फिर इसका हल चीन के आर्थिक हितों को प्रभावित करने में निहित है, जिसका भारत के साथ सालाना कारोबार सौ अरब डालर के आसपास है?

माकूल जवाब कैसा हो?

भारत सरकार स्पष्ट रूप से बड़ी मुश्किल स्थिति में है। अगर सीमा पर बल-प्रयोग किया जाता है तो संभव है कि स्थिति गंभीर होकर युद्ध में बदल जाए। और अगर चीनी घुसपैठ को ज्यादा दिन अनदेखा किया जाता है तो हो सकता है कि वे धीरे-धीरे अपने पाँव दूसरे इलाकों में भी पसार लें, जैसा उन्होंने १९५९ की लड़ाई से पहले किया था और जैसा वे अपने दूसरे पड़ोसी देशों के मामले में करते रहे हैं। भारत सरकार की पहली प्राथमिकता इस राजनैतिक समाधान की ही होगी, लेकिन फिलहाल वह विकल्प काम करता नहीं दिखता। भारत राजनयिक जरियों से अपनी नाराजगी प्रकट कर चुका है। ऐसे में, विरोध प्रदर्शन का अगला चरण विदेश मंत्री की चीन यात्रा को रद्द करना हो सकता है। इसके बाद कुछ सांकेतिक आर्थिक कदम उठाए जा सकते हैं। लेकिन अगर उससे भी चीन के रुख में बदलाव न आए तो भारत को सन बासठ की गलती दोहरानी नहीं चाहिए और चीन के सामने अपनी सैन्य शक्ति के प्रदर्शन से झिझकना नहीं चाहिए। आज का भारत बासठ वाला भारत नहीं है जब हम युद्ध लड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे।

आज हम एक परमाणु शक्ति हैं और न्यूक्लियर ट्रायड की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हमारी फौजें आधुनिक लड़ाकू विमानों से लेकर परमाणु-आयुध सम्पन्न मिसाइलें और जंगी जहाजों से लेकर परमाणु पनडुब्बी तक से लैस हैं। चीन सीमा के आसपास सड़कों का जाल, हवाई पट्टियां और दूसरी ढाँचागत सुविधाएँ मौजूद हैं। आर्थिक दृष्टि से भी कोई समस्या नहीं है। ऐसे में, भले ही चीन से युद्ध हमारा मकसद नहीं है लेकिन झुकते चले जाने की भला कौनसी मजबूरी है? सन १९८६ की घटना याद कीजिए जब जनरल कृष्णास्वामी सुंदरजी थल सेनाध्यक्ष थे और चीनी घुसपैठ का दमदार फौजी जवाब दिया गया था। आज तो हालात बहुत अलग हैं। तब चीन ने अरुणाचल प्रदेश में समदूरोंग चू के पहाड़ी इलाके पर कब्जा कर लिया था। जनरल सुंदरजी ने भारतीय वायुसेना की मदद लेते हुए तवाँग के उत्तरी इलाके में भारतीय टुकड़ियों को उतारा और दोनों देशों के फौजी आमने-सामने डटे रहे। कठोर रुख दिखाने के लिए जनरल सुंदरजी की आलोचना भी हुई लेकिन आखिरकार चीनियों को लौटना पड़ा। ऐसी और भी घटनाएँ हुई हैं, जब हमारे सैन्य कमांडरों ने अपने आत्मविश्वास और संकल्प का परिचय दिया।

सरकार को जन-भावनाओं के दबाव में आकर फैसला करने की जरूरत नहीं है और न ही युद्ध का माहौल बनाने की। लेकिन उसे मजबूती से यह संदेश जरूर भेजना चाहिए कि भारत कोई कमजोर राष्ट्र नहीं है और वह दबने के लिए तैयार नहीं है। हमें अपनी बात को मजबूती से रखने और सभी विकल्प खुले रखने के लिए तैयार रहना होगा।

बताया जाता है कि तीसरी फ्लैग मीटिंग में चीनी फौजी अफसरों ने मांग की कि भारत पूर्वी लद्दाख में बनाई सुविधाओं को खत्म करे, जिनमें सड़कें और बंकर शामिल हैं। भारत ने यह मांग नहीं मानी क्योंकि खुद चीन भारत के साथ लगने वाली सीमा पर सड़कों, रेल लाइनों और हवाई पट्टियों का जाल बिछा चुका है। अपनी सुरक्षा के लिए बढ़ी चुनौती के जवाब में भारत निष्क्रिय बैठे रहने का जोखिम नहीं उठा सकता जिसके ३८ हजार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर पहले ही चीन ने कब्जा कर रखा है।